

न्यायालय असिस्टेंट कलेक्टर प्रथम श्रेणी, मोहनलालगंज, लखनऊ।

वाद संख्या-284/12-13
दर्शन आदि बनाम सरकार
धारा- 143 ज0वि0अधि0
ग्राम -बेली

निर्णय

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही दर्शन पुत्र धुरु व श्रीमती रामरानी पत्नी दर्शन नि0गण-बेलीखुर्द परगना व तहसील मोहनलालगंज, लखनऊ के प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रारम्भ की गई। जिसमें अवगत कराया गया कि प्रार्थीगण के नाम भूमि गाटा संख्या- 263/0.047,270मि/0.169हे0 व 273/0.051हे0स्थित ग्राम बेली परगना व तहसील मोहनलालगंज, लखनऊ पर खेती नहीं हो रही है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि पर कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, बागवानी के उपयोग में नहीं लाई जा रही है बल्कि अन्य उपयोगिता में लाई जा रही है। प्रार्थीगण द्वारा भूमि गाटा संख्या- 263/0.047,270मि/0.169हे0 व 273/0.051हे0स्थित ग्राम बेली परगना व तहसील मोहनलालगंज, लखनऊ को अकृषिक घोषित किए जाने का अनुरोध किया गया।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र पर तहसीलदार मोहनलालगंज से प्राप्त आख्या दिनांक 29.08.2013 में अवगत कराया गया कि प्रश्नगत उल्लिखित गाटा संख्या संकमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है। उक्त गाटा संख्या के प्रश्नगत भाग पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है मौके पर प्लाटिंग हो रही है। भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित महायोजना के अन्तर्गत नोटिफाइड ग्राम की है किन्तु अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित नहीं है। उक्त गाटा संख्या का रकबा सरकारी भूमि नहीं है। सीमा सम्बन्धी विवाद नहीं है। भूमि का कोई वाद नहीं है। आख्या में प्रार्थीगण के नाम भूमि गाटा संख्या- 263/0.047,270मि/0.169हे0 व 273/0.051हे0स्थित ग्राम बेली परगना व तहसील मोहनलालगंज, लखनऊ को अकृषिक घोषित किए जाने हेतु आख्या प्रेषित की गई।

वाद दर्ज कर नियमानुसार लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ को नोटिस जारी की गई जो कि सम्यक रूप से तामील होकर प्राप्त हुई। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। पत्रावली का अवलोकन व परिशीलन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्राप्त आख्या में अवगत कराया गया कि प्रश्नगत उल्लिखित गाटा संख्या संकमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है। उक्त गाटा संख्या के प्रश्नगत भाग पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है तथा प्लाटिंग हो रही है। अतः तहसीलदार मोहनलालगंज से प्राप्त आख्या के आधार पर प्रार्थीगण के नाम भूमि गाटा संख्या- 263/0.047,270मि/0.169हे0 व 273/0.051हे0स्थित ग्राम बेली परगना व तहसील मोहनलालगंज, लखनऊ को अकृषिक घोषित किया जाना विधि संगत प्रतीत होता है परन्तु भूमि उपयोगिता की विधिमान्यता के सम्बन्ध में लखनऊ महायोजना 2021 के उपबन्ध प्रभावी होंगे जिसका सम्बन्ध लखनऊ विकास प्राधिकरण व शहरी नियोजन विभाग से है।